नईदुनिया

अधिकारी वही, जो जनहित के करें कार्य

मुख्यमंत्री ने 3 विभागों के 362 अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अधिकारी वह है, जो जनहित में कार्य करें। इस उद्देश्य से शासकीय सेवा में प्रवेश करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, स्वयं को प्रधान सेवक मानते हैं।

प्रदेश का मंत्रि-मंडल भी परस्पर सहयोग से जनता के सेवक के रूप में कार्य कर रहा है। पद पर आने के बाद हमारे मन में अहंकार नहीं होगा, इस संकल्प के साथ, समाज हित और प्रदेश के विकास के लिए समर्पित होकर अपने दायित्व निर्वहन में आगे बढ़ें। डॉ.

यादव शुक्रवार को रवीन्द्र भवन में कृषि, पशुपालन और राजस्व विभागों के लिए चयनित 362 शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को नियुक्ति-पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माता-पिता सहित परिवार के सदस्यों की आशा, अपेक्षा और उनके सहयोग के परिणामस्वरूप ही यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के 256 कृषि विस्तार अधिकारी, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के 70 सहायक पशु चिकित्सकों और राजस्व विभाग के 36 नव चयनित नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कृषि विस्तार अधिकारी प्रियंवदा द्विवेदी, कमलेश वाटी, राजेश मीणा, सुश्री बबली बागरी, सुश्री अर्चना गौर, सहायक पशु चिकित्सक डॉ. पूजा सोलंकी, डॉ. नीतेश सूर्यवंशी, डॉ. राहुल यादव और नायब तहसीलदार सुश्री भारती सोलंकी, रवि पटेल, कपिल गुर्जर को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।

आर्मी मैराथन में अधिक से अधिक आमजन करें सहभागिताः सारंग

भोपाल(काप्र)।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने 19 जनवरी को होने वाली ऑर्मी मैराथन के संबंध में शुक्रवार को निजी और शासकीय विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की।

उन्होंने सभी विश्वविद्यालय के युवा एवं फैकल्टी को फिट रहने के लिये मैराथन में भागीदारी करने की अपील की। सभी ने फिट रहने के लिये इसमें भागीदारी करने की सहमति प्रदान की। श्री सारंग ने भोपालवासियों से अधिक से अधिक संख्या में मैराथन में सहभागिता करने का आव्हान किया। श्री सारंग ने कहा कि स्वच्छ भारत, हरित भारत, फिट इंडिया के लिये भारतीय सेना के साथ दौड़ें। यह सहन शक्ति, दृढ़ संकल्प और विजय की परिचायक बने। उन्होंने बताया कि मैराथन अपने आदर्श वाक्य फिट इंडिया, रन विद इंडियन ऑर्मी के माध्यम से भारत सरकार के फिट इंडिया एकता और देशभक्ति के अभियान को बढ़ावा देगा। मैराथन में 3 श्रेणी रखी गई है इसमें 21 किमी, 10 किमी और 5 किमी के लिये न्यूनतम शुल्क पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। सहभागियों को टी-शर्ट और ऑर्मी मैराथन में भाग लेने का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा। यही नहीं संस्था, विश्वविद्यालयों को भी इसका प्रमाण-पत्र मोमेन्टो के साथ प्रदाय किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मैराथन भोपाल स्थित द्रौणांचल से वीआईपी रोड होते हुए द्रौणांचल पर समाप्त होगी। श्री सारंग ने सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों से संबंधित संस्था एवं संस्थानों के सोशल मीडिया एकाउन्ट से व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा है।

कल्चर ऑफ फिटनेस को बढ़ावा

ऑर्मी मेजर जनरल सुमित कबथियाल ने कहा कि श्री सारंग के माध्यम से राज्य सरकार का सहयोग मिल रहा है। यह मैराथन कल्चर ऑफ फिटनेस को बढ़ावा देगी और फिट रहने एवं हेल्थ के प्रति जागरूक करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि द्रौणांचल में युद्धस्थल के माध्यम से युद्ध के इतिहास और शहीदों के बारे में जानकारी भी अर्जित होगी। उन्होंने बताया कि मैराथन में एनसीसी के ही लगभग 600 रजिस्ट्रेशन हो चुके है। मैराथन सभी के लिये है, इसमें परिवार, दोस्त सभी भागीदारी कर सकते हैं।

10 लाख रुपए तक का पुरस्कार

ऑर्मी मैराथन सुबह 6 बजे से शुरू होगी। इसमें सभी क्षेत्रों से लगभग 12 हजार प्रतिभागी तीनों श्रेणियों की दौड़ में हिस्सा लेंगे। आकर्षक प्रायोजित पुरस्कारों के अलावा 10 लाख रूपये तक के नकद पुरस्कार भी दिये जायेंगे। हॉफ मैराथन में विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं के लिये 5,30,000 रूपये के नकद पुरस्कार, 10 किमी में विभिन्न श्रेणी के विजेताओं को 2,64,000 रूपये और 5 किमी में 1,87,000 रूपये के नकद पुरस्कार दिये जायेंगे।

मकर संक्रांति से आरंभ होंगे महिलाओं की बेहतरी के लिए कार्यक्रमः मुख्यमंत्री

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब युवा शक्ति किसान और नारी के जीवन में बदलाव लाने के लिए चारों मिशन पर कार्य कर रही है। विशेषकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में मकर संक्रांति पर्व पर एक वृहद कार्यक्रम प्रस्तावित है। स्व रोजगार व स्वावलंबन के माध्यम से आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए महिलाओं को सशक्त करना हमारा उद्देश्य है।

डॉ. यादव ने कहा कि नारी सशक्तिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही लाड़ली बहनों को दिए जा रहे अनुदान की राशि में भी वृद्धि की गई थी। बहनों की स्थिति में उत्तरोत्तर उन्नति के उद्देश्य से उद्योग, स्वावलंबन और स्व-सहायता समूह की गतिविधियों जैसे आयाम भी जोड़े जा रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट्स सहित अन्य उद्योगों में महिला श्रम आधारित ऐसे कार्य आरंभ किए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे और उन्हें बेहतर जीवन का अवसर प्राप्त हो सकेगा। प्रदेश में इस प्रकार के चार उद्योग आरंभ किए जा चुके है, साथ ही गतिविधियों का और विस्तार किया जा रहा है। इन उद्योगों को राज्य सरकार की ओर से प्रति श्रमिक पाँच हजार रूपए इंसेंटिव की व्यवस्था है। डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश और देश की उन्नति में सब सहभागी हों, इसी भाव से राज्य सरकार विकास और जनकल्याण की दिशा में सक्रिय है। हमारा विश्वास है कि सबके समन्वित प्रयास से ही प्रदेश की तकदीर बदलेगी।

शहीद रामसिया के वारिसों को 10 लाख की सहायता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के सुकमा कोटा क्षेत्र में वर्ष 2005 में ड्यूटी के दौरान नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद होने वाले सीधी जिले के सिहावल तहसील निवासी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान रामसिया मिश्रा के निकटतम वारिसों को 10 लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की। डॉ. यादव के निर्देश पर यह सहायता व्यक्तिगत आर्थिक नियमों को शिथिल करते हुए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से प्रदान की गई। डॉ. यादव ने कर्तव्यनिष्ठा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीद को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राज्य सरकार शहीद के परिजन के साथ है। उल्लेखनीय है कि सिंहावल विधायक विश्वामित्र पाठक द्वारा 2005 का यह मामला हाल ही में मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया था।

अब तक 6 लाख 4 हजार बिजली उपभोक्ताओं ने कराई ई-केवायसी

भोपाल (काप्र)। राज्य शासन की लाभकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपाय ऐप के जरिए भी ई-केवायसी करा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध उपाय ऐप डाउनलोड कर बिजली उपभोक्ता समग्र केवायसी में अपना उपभोक्ता क्रमांक एवं समग्र क्रमांक दर्ज करने के बाद लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज कर केवायसी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। केवायसी प्रक्रिया के तहत अब तक 6 लाख 4 हजार 399 उपभोक्ताओं ने सफलतापूर्वक केवायसी करा ली है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के बिजली संबंधी व्यक्तिगत विवरण को कंपनी के रिकार्ड में अपडेट करने के लिए नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया शुरू की है। कंपनी द्वारा नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया के तहत बिजली उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी जैसे समग्र आईडी, मोबाइल नंबर एवं बैंक खाता इत्यादि की जानकारी को अपडेट किया जा रहा है।

सांस्कृतिक पहचान और गौरव की प्रतीक है हिंदी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विश्व हिंदी दिवस, सांस्कृतिक पहचान और गौरव की प्रतीक हिंदी भाषा के वैश्विक जय घोष के विचारों को आत्मसात करने का दिन है। डॉ. यादव ने विश्व हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने हिंदी भाषा के रूप में मिली विरासत को और अधिक समृद्ध करने के लिए संकल्पित होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रदेशवासियों से आव्हान किया है। डॉ. यादव ने मीडिया को जारी संदेश में कहा कि हिन्दी दिवस अपने आप में विशेष है। अब हिन्दी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। संपूर्ण विश्व में हिन्दी का महत्व तथा लोगों की हिन्दी के प्रति रूचि बढ़ी है। यूरोप हो या चीन सभी देश नई तकनीकी माध्यमों का उपयोग करते हुए अनुवाद के माध्यम से हिन्दी तक अपनी पहुंच बना रहे हैं, यह हम सब के लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है।

मप्र एटीएस के 9 पुलिसकर्मी निलंबित

हरियाणा में होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर टेरर फंडिग के आरोपी की मौत का मामला

भोपाल(काप्र)।

हरियाणा के गुरुग्राम के सोहना में एक होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर हुई युवक की मौत के मामले में एमपी एटीएस की मुश्किले बढ़ गई है।

घटना में जहाँ मृतक युवक बिहार निवासी हिमांशु (23) के चाचा चंदन कुमार की शिकायत पर मप्र एटीएस पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। वहीं मामले को लेकर सोहना पुलिस ने भी मौत के कारणो की छानबीन शुरु करते हुए होटल के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने ज्यूडिशियल जांच शुरू कर दी है। इधर एडीजी इंटेलिजेंस योगेश देशमुख ने मप्र एटीएस टीम के नौ सदस्यों को निलंबित कर दिया है, जिसमें इंस्पेक्टर, हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल शामिल हैं। गौरतलब है कि टेरर फंडिंग और साइबर क्राइम के मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया था। बिहार निवासी हिमांशु भी मप्र टेरर फंडिंग और साइबर क्राइम से जुड़े छह आरोपियों में से एक था। एमपी एटीएस ने सभी आरोपियों से 14 लैपटॉप, एक टैबलेट, 41 मोबाइल और 85 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि हिमांशु और एक अन्य आरोपी पूरे नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी थे, जबकि चार अन्य उनके सहयोगी थे। मामले की जांच मप्र साइबर सेल और एटीएस की ओर से की जा रही है। घटना को लेकर जहाँ मध्यप्रदेश एटीएस का कहना है की हिमांशु बाथरूम जाने के बहाने तीसरी मंजिल की गैलरी में आया और वहां से बिजली केबल के सहारे नीचे की ओर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह केबल को पकड़ नहीं पाया और सिर के बल नीचे गिरा जिससे उसके सिर में घातक चोट आई थी। एटीएस ने उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय पुलिस को उसकी मौत की जानकारी अस्पताल से मिली। वहीं मृतक हिमांशु के परिजन ने एटीएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिमांशु के चाचा चंदन कुमार ने सोहना पुलिस को दी शिकायत में कहा कि हिमांशु दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि मप्र एटीएस ने हिमांशु और उसके साथियों को होटल में रखा और फिर उसे तीसरी मंजिल से फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एटीएस के पास हिमांशु को हिरासत में लेने के लिए कोई वारंट भी नहीं था। इधर साइबर क्राइम टीमे इस बात की लगातार जॉच कर रही है की आरोपियों का टेरर लिंक था या नहीं।

श्रमिकों को अप्रैल-24 से ही मिलेगा न्यूनतम पुनरीक्षित वेतन

भोपाल (काप्र)। प्रदेश के आउटसोर्स और अस्थाई कर्मचारियों सहित 35 लाख से अधिक श्रमिकों को 1 अप्रैल 2024 से ही न्यूनतम पुनरीक्षित वेतन का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के 3 दिसंबर 2024 के आदेश पर श्रमायुक्त ने राज्य शासन से अभिमत मांगा था। सरकारी अधिवक्ता भुवन गौतम ने राय दी है कि जिस स्थगन के तहत विवादित अधिसूचना के कार्यान्वयन को अस्थाई रूप से रोक दिया गया था, उसे हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर-24 को निरस्त कर दिया। इसलिए लाभार्थियों को विवादित अधिसूचना का लाभ 1 अप्रैल 2024 से दिया जाना चाहिए। प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने साल 2019 में श्रमिकों का वेतन 25 प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2024 से इस सिफारिश को लागू किया। श्रमिकों को एक माह ही बढ़ा हुआ वेतन मिल पाया और एमजी टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने 4 मार्च-24 को जारी वेतनवृद्धि की अधिसूचना की वैधता को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में चुनौती दे दी। प्रकरण की सुनवाई 8 मई-24 को हुई और हाईकोर्ट ने वेतनवृद्धि की अधिसूचना के संचालन व कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। वेतनवृद्धि का लाभ दिलाने के लिए सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) एवं अन्य ने याचिका लगाई। वहीं राज्य शासन ने याचिका पर जवाब दाखिल किया, जिसमें वेतनवृद्धि की अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही को उचित ठहराया गया। 3 दिसंबर-24 को प्रकरण हाईकोर्ट में फिर से सूचीबद्ध हुआ और सुनवाई के बाद कोर्ट ने 8 मई-24 के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया।

नर्मदा नदी में क्रूज चलाने की तैयारियां तेज

मेघनाद घाट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक क्रूज चलाने टेंडर निकाले

भोपाल (काप्र)।

नर्मदा नदी में क्रूज चलाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मप्रपर्यटन विभाग ने बड़वानी से लगे धार जिले के नर्मदा किनारे स्थित मेघनाद घाट से गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक नर्मदा नदी में क्रूज संचालन हेतु निविदा जारी कर दी है। सांसद सुमेरसिंह सोलंकी ने बताया कि पर्यटन विभाग ने सफर की तीन श्रेणियां बनाई हैं।

पहली श्रेणी में पांच दिन के सफर की एक श्रेणी रखी है। इसमें रात्रि विश्राम, भोजन, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इसका मार्ग सरदार सरोवर बांध से हापेश्वर-मेघनाद घाट-साकरेज-स्टैच्यू आफ यूनिटी तक का रहेगा। इसकी दूरी 270 किमी होगी। सफर की दूसरी श्रेणी एक तरफा क्रूज यानी तीन दिन का सफर। सरदार सरोवर बांध से हापेश्वर-साकरेजा- मेघनाद घाट तक का सफर किया जा सकेगा। इसकी दूरी 135 किमी होगी। तृतीय श्रेणी में क्रूज का सफर केवल दो घंटे का होगा। क्रूज से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। मेघनाद घाट से 10 किमी परिधि में ही सफर करवाया जाएगा। इस छोटे पैकेज में स्थानीय साइड सीन और नाश्ते की व्यवस्था उपलब्ध होगी।

चार प्रमुख स्थानों पर बनेंगे जेटी स्टेशन

135 किमी लंबे जलमार्ग पर चार स्थानों को क्रूज संचालन के लिए जोड़ा जाएगा। यह जलमार्ग बड़वानी से लगे धार जिले के मेघनाद घाट से शुरु होकर अलीराजपुर जिले के साकरेजा, गुजरात के हापेश्वर होते हुए स्टैच्यू आफ यूनिटी तक जाएगा। इन स्थानों पर जेटी स्टेशन(पोंटून) बनाए जाएंगे, ताकि पर्यटकों को क्रूज पर आने-जाने की सुविधा मिल सके। वर्तमान में प्रदेश में बनने वाले दो स्टेशन के लिए जेटी पोंटून आ गए हैं और ये मेघनाद घाट पर नदी में खड़े हैं।

छोटे स्टेशन भी बनाए जाएंगे

सांसद ने बताया कि बड़वानी, अंजड़ और धरमपुरी में भी छोटे स्टेशन बनाना प्रस्तावित है जो मुख्य स्टेशन मेघनाद घाट से जुड़ेंगे। निजी एजेंसियों को इस परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी तय की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत साल 2026 के अंत तक पहले अंतर-प्रांतीय जल मार्ग पर पर्यटन शुरू होने की उम्मीद है। क्रूज मार्ग पर अलीराजपुर जिले के साकरेजा और गुजरात के हापेश्वर जेटी पाइंट्स पर पर्यटकों को आदिवासी बहुल गांवों में होम स्टे की व्यवस्था भी होगी।

जिला कार्यालयों में भी अनिवार्य रूप से लागू होगी ई-ऑफिस प्रणाली

भोपाल (काप्र)। राज्य शासन मंत्रालय में 1 जनवरी से पूर्णतः ई-ऑफिस प्रणाली लागू हो चुकी है। जिसके तहत मुख्य सचिव कार्यालय में कोई भी फाइल भौतिक रूप से स्वीकार नहीं की जा रही है। सभी फाइलों को ई-ऑफिस के जरिए ही बुलाया जा रहा है। अब अगले चरण में सभी विभागाध्यक्ष कार्यालय और जिला कायालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी तक विभागाध्यक्ष कार्यालय और 31 मार्च 2025 तक सभी जिला कार्यालयों में पूर्णतः ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जानी है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने सभी विभागों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य शासन ने सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है। इसके लिए कर्मचारी मास्टर डाटा का अद्यतन करा लें। इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है। सभी विभागों से कहा है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर ई-ऑफिस प्रणाली का अनिवार्य रूप से संचालन शुरू कर दें। इसी अवधि में शासन के सभी संभागीय कार्यालयों में भी ई-ऑफिस प्रणाली लागू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार 1 अप्रैल से प्रदेश का कोई भी जिला कार्यालय जहां से राज्य शासन या अन्य उच्च कार्यालय को नस्ती भेजी जाएगा तो सिर्फ ई-ऑफिस से भेजी जाएगी। नई नस्ती भौतिक रूप में उच्च कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी।

स्पेशल खबर *मुख्यमंत्री ने किया दो दिवसीय आईएफएस मीट और वानिकी सम्मेलन का शुभारंभ...*

वनक्षेत्र-वन्यजीवों की गतिविधियों में वृद्धि प्रदेश की उपलब्धिः डॉ. यादव

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के पन्ना जैसे क्षेत्र जहां वन्य जीवों की स्थिति शून्य हो गई थी, वहां भी वन अधिकारियों के प्रयासों के परिणामस्वरूप वन्य जीवों की गतिविधियां पुनः आरंभ हुई, यह अपनी सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है और वे बधाई के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के पास हीरा है, चीता है और अब तो गजराज भी मध्यप्रदेश का रूख कर रहे हैं। प्रदेश का वन क्षेत्र समृद्ध है। वर्ष 2003 से 2021 के मध्य वन क्षेत्र में 1063 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भोपाल देश की एकमात्र ऐसी राजधानी है, जिसके आस-पास आसानी से टाइगर देखे जा सकते हैं। यह हमारे प्रदेश के लिए सुखद और पर्यावरण की दृष्टि से बड़ी उपलब्धि है। डॉ. यादव पं. खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय सभागार में दो दिवसीय भारतीय वन सेवा मीट और वानिकी सम्मेलन के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। दीप प्रज्ज्वलन तथा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार, अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख असीम श्रीवास्तव उपस्थित थे। मुख्यमंत्री को रूद्राक्ष का पौधा भेंटकर उनका स्वागत किया गया। डॉ. यादव ने कहा कि इस प्रकार के मीट परस्पर संवाद, मित्रता के भाव, अनुभव साझा करने और

बेहतर कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए आवश्यक हैं। प्रदेश में प्रचुर वन संपदा विद्यमान है तथा पुरातत्व, भू-गर्भ शास्त्र, पर्यावरण, वनस्पति शास्त्र सहित कई विधाओं में अध्ययन व शोध की अपार संभावना विद्यमान हैं। वन विभाग को इन क्षेत्रों में अध्ययन को प्रोत्साहन और सहयोग प्रदान करने के लिए पहल करना होगी। इसी प्रकार पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए भी गतिविधियों का विस्तार किया जाए। उन्होंने रातापानी के संदर्भ में ग्रामों के विस्थापन की चुनौती का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए वन अमले की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा वनों के विकास और नवाचारी गतिविधियों के संचालन के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1,भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com